भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1641
10.03.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय वन नीति

1641. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख तक देश भर में वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का वर्तमान प्रतिशत कितना है;

(ख) राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के वन एवं वृक्ष आच्छादन को 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन में हाल के घटनाक्रमों के अनुरूप प्रावधानों को नवीनीकृत करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) - 2023 के अनुसार, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% भाग वन और वृक्ष आच्छादित है।

(ख) मंत्रालय हरित भारत मिशन, नगर वन योजना, वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा), नगर वन योजना (एनवीवाई) और तटीय पर्यावास और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देश भर में वृक्षारोपण कार्यकलापों को शुरू करने के लिए जून, 2024 के दौरान "एक पेड़ माँ के नाम" नामक वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया गया था।

संबंधित मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन आदि तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की योजनाओं के तहत भी वनरोपण कार्यकलाप किए जाते हैं। बहु-विभागीय प्रयासों से देश में वन क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन में अच्छे परिणाम मिले हैं।

(ग) और (घ) भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई विभिन्न क्षेत्रों में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में अंतर्निहित है। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जलवायु संबंधी सभी कार्यकलापों के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है और इसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा के कुशल उपयोग में वृद्धि, संधारणीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संधारणीयता, हरित भारत, संधारणीय कृषि, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक जानकारी के विशिष्ट क्षेत्रों में संचालित मिशन शामिल हैं। इन सभी मिशनों को उनके संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत और कार्यान्वित किया जाता है।

*****